विवाद

संचालकों का भुगतान रुका, सहयोग से इंकार, प्रशासन ने दी अधिग्रहण की चेतावनी

धान खरीदी से पहले प्रशासन-वेयरहाउस में टकराव

नवभारत, जबलपुर। जिले में धान उपार्जन शुरू होने से पहले ही प्रशासन और वेयरहाउस संचालकों के बीच विवाद गहरा गया है। वेयरहाउस संचालकों का कहना है कि तीन वर्षों से 425 वेयरहाउसों का करीब 130 करोड़ रुपये किराया लंबित है। भुगतान न मिलने की वजह से वे आर्थिक संकट में हैं और इस स्थिति में धान खरीदी में सहयोग करना संभव नहीं है। संचालकों का कहना है कि लंबित राशि के कारण वे बैंक ऋण, कर्मचारियों के वेतन और अन्य दैनिक खर्चों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जब तक भुगतान नहीं किया जाता, वे इस वर्ष उपार्जन कार्य में सहयोग नहीं देंगे।

खरीदी के लिए नहीं देंगे वेयरहाउस : संचालक

वेयरहाउस एसोसिएशन ने बताया कि 3 सालों से किराया नहीं मिलने से वह आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कई बार शासन-प्रशासन से मांग करने और धरना प्रदर्शन के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि जब तक भुगतान को लेकर कोई कुछ ठोस कार्यवाही नहीं होती है तब तक वह उपार्जन में ना तो धान भंडारण की अनुमति देंगे, ना ही धान खरीदी के लिए अपने वेयरहाउस में केंद्र बनने देंगे।

सहयोग नहीं तो अधिग्रहण की कार्रवाई : प्रशासन

प्रशासन ने वेयरहाउस संचालकों की चेतावनी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि धान उपार्जन की तैयारियां चल रही हैं। यदि वेयरहाउस संचालक सहयोग नहीं करते हैं, तो अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि संचालकों के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही उनका भुगतान हो जाएगा।

इनका कहना है

धान उपार्जन की तैयारी चल रही है, नान के डीएम की पदस्थापना की जा चुकी है। धान खरीदी में कोई समस्या नहीं आएगी, अधिग्रहण का भी विकल्प रहता है, जरूरत पड़ने पर वेयरहाउसों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अंतर्गत लंबित भुगतान को लेकर ही काम चल रहा है, जल्द भुगतान भी किया जाएगा।

राघवेंद्र सिंह
कलेक्टर

अब काशी एक्सप्रेस में मिली बम होने की सूचना

जबलपुर, नवभारत। गोरखपुर से मुंबई के लिए रवाना हुई गाड़ी संख्या 15018 काशी एक्सप्रेस मे मंगलवार को बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। ट्रेन में बम की सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने भदोही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया।यहाँ तक की यात्रियों को भी डिब्बों से उतारा गया। रेल सूत्रो से मिली जानकारी अनुसार रेलवे कंट्रोल रूम को एक लैंडलाइन फोन से कॉल करके बताया गया कि गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15018 ट्रेन में बम रखा है कॉल के बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया ट्रेन के भदोही पहुंचते ही यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया और सभी को प्लेटफॉर्म पर रोक दिया गया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने कोच दर कोच तलाशी ली सुरक्षाकर्मियों ने ट्रेन की बोगियों और शौचालयों और सामान रखने वाले हिस्सों तक की गहन जांच की और घटना के बाद स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

प्रदेश बदलने से क्या जाति बदल जाती है?

हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या दूसरे प्रदेश में बसने से किसी व्यक्ति की जाति बदल जाती है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने एक कर्मचारी के गौंड जनजाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित किये जाने को चुनौती देने वाले मामले में उक्त जवाब तलब किया है। यह मामला जबलपुर निवासी विश्वनाथ साह की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि उनका जन्म 1966 में जबलपुर में हुआ था। इसके पूर्व याचिकाकर्ता के माता-पिता बिहार के सिवान जिले से पलायन कर यहां आए थे। मजदूरी कर वह अपने परिवार का पालनपोषण करते थे। वर्ष 1981 में तत्कालीन कलेक्टर जबलपुर ने याचिकाकर्ता को उसके माता-पिता की जाति के आधार पर गोंड जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। आवेदक की ओर से कहा गया कि राज्य स्तरीय उच्च-शक्ति समीक्षा समिति ने 5 अगस्त 2025 के अपने आदेश में केवल इस आधार पर उनके जनजाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया कि उनके पिता का जन्म बिहार में हुआ था।

याचिकाकर्ता का जन्म, शिक्षा और पूरा जीवन जबलपुर, मध्य प्रदेश में ही बीता है और उन्हें 1981 में ही जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। याचिका में अंतर-राज्यीय प्रवासियों के संबंध में जारी केंद्र और राज्य सरकार की उन अधिसूचनाओं और परिपत्रों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जिनके अनुसार किसी अन्य राज्य में प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को मूल राज्य के स्थान पर प्रवासी राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में प्राप्त उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह व परमानंद साहू ने पक्ष रखा।

भवन निर्माण
₹ 1500/- वर्गफुट कंस्ट्रक्शन
माड्यूलर किचिन लेटबाथ स्टील रेलिंग बिजली पानी, मटेरियल सहित, कम्पलीट वर्क
संपर्क करे
कमलेश पटेल- मो.नं. 6260334877

नौनिहालों को राहत : सुबह 9 बजे के बाद लगेगी स्कूल

▶ शीतलहर की चपेट में शहर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

नवभारत, जबलपुर। शहर शीतलहर की चपेट में हैं। ठंडी हवाएं ठुठरन बढ़ा रही हैं। तापमान में हो रही गिरावट और ठंड का असर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने नौनिहालों को राहत दे दी हैअब जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज से कक्षा नर्सरी से पांचवीं तक की कक्षाएं प्रातः 9 बजे या इसके पश्चात प्रारंभ होंगी। इसी प्रकार छटवीं से 12वीं तक की कक्षाएं प्रातः 8:30 बजे से प्रारंभ की जाएंगी। इसके अलावा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी परिवर्तित किया है। आंगनबाड़ी केंद्र अब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेंगे। बच्चों की उपस्थिति के लिये सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया है। जबकि, शेष तीन घण्टे में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गृह भेंट, रिकार्ड संधारण एवं अन्य विभागीय कार्यों को संपादित करेंगी।

मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को कोमोरियन और निकटवर्ती क्षेत्रों में निम्न दाब क्षेत्र अवस्थित है और इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 5.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। 22 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद, इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 48 घंटों के दौरान और अधिक स्पष्ट होने की प्रबल संभावना है।

ऐसा रहा तापमान

मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 82 और शाम को 63 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तर हवाएं 4 किमी की रफ्तार से चली।

एसआईआर कार्य में लापरवाही, दो बीएलओ और एक पटवारी निलंबित

नवभारत, जबलपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो बीएलओ और एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों पर आदेशों की अवहेलना और निर्धारित दायित्वों का निर्वहन न करने का आरोप है। निलंबित बीएलओ में विधानसभा क्षेत्र जबलपुर केंट के मतदान केंद्र क्रमांक 150 के बीएलओ एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सहायक ग्रेड-3 संदीप नंदा, तथा विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर के मतदान केंद्र क्रमांक 133 की बीएलओ एवं वन विभाग की वन रक्षक मोनू भारती शामिल हैं। वहीं शहपुरा तहसील के हल्का नंबर 35 रमखिरिया ठूंठा के पटवारी आशुतोष चतुर्वेदी को बीएलओ के सत्यापन कार्य में सहयोग न करने के कारण निलंबित किया गया है।

एक अधिकारी सहित आठ बीएलओ को कारण बताओ नोटिस

एसआईआर प्रणाली में गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन कार्य की धीमी प्रगति पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्य में संतोषजनक प्रगति न होने पर एक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं आठ बीएलओ सुपरवाइज़र्स को कारण-बताओ नोटिस जारी किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योति परस्ते ने बताया कि संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों से 19 नवम्बर दोपहर 12 बजे तक लिखित जवाब मांगा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

उन्नत कृषि, समृद्ध किसान
विकसित भारत का निर्माण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा
पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत
₹18,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि
9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर एवं
दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती समिट 2025 का उद्घाटन

19 नवम्बर, 2025 | दोपहर 1:00 बजे | कोयम्बत्तूर, तमिलनाडु

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- किसानों के खातों में तीन समान किस्तों में **प्रतिवर्ष ₹6,000** की सीधी सहायता
- अब तक **₹3.90 लाख करोड़ से अधिक की राशि** सीधे **किसानों** के बैंक खातों में ट्रांसफर
- पीएम किसान के लाभार्थियों में **25% महिला किसान**
- विश्व की सबसे बड़ी **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांफसर (DBT)** योजनाओं में से एक
- पीएम किसान के **85%** से अधिक लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान

कृषि में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ
- बीते 11 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन 246 मिलियन टन से बढ़कर **354 मिलियन टन** हुआ
- **25 करोड़** से अधिक **सॉइल हेल्थ कार्ड**
- **100 लाख हेक्टेयर** में सूक्ष्म सिंचाई
- **₹2 लाख करोड़** की फसल बीमा सहायता
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत **55 हज़ार** से अधिक किसानों का प्रमाणीकरण
- पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह ₹ 6.35 लाख करोड़ से बढ़कर करीब **₹16 लाख करोड़** हुआ
- नई तकनीक, एफपीओ, किसानों की डिजिटल आईडी, पीएम आशा और एआईएफ के साथ ग्रामीण भारत में बड़ा सकारात्मक बदलाव

कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश
- ₹24,000 करोड़ की राशि से **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना** संचालित
- ₹11,440 करोड़ की राशि से **दलहन आत्मनिर्भरता मिशन** को प्रोत्साहन
- पिछले 11 वर्षों में कृषि बजट में लगभग **5 गुना** बढ़ोतरी, ₹22,000 करोड से बढ़कर **₹1.27 लाख करोड़** हुआ
- पिछले 11 वर्षों में लगभग **₹14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी** से किसानों को सही समय और किफायती दामों पर खाद की आपूर्ति

CBC 01102/13/0007/2526

बीज से बाजार तक भारत सरकार किसानों के साथ

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज़, डीडी किसान चैनल www.youtube.com/@AgriGoi पर देखें
न्यूज़ किसान
फॉलो करें: @AgriGoI
अधिक जानकारी के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57